be made far more vibrant and relevant in the context of various plantations that are, now, reaching their maximum potential, for which the Ministry has officially formed a Committee as of March, this year, with a timeline given that within four months they will give us a report on how the curriculum can be made relevant and far more pertinent for plantation management.

SHRI T. G. VENKATESH: Respected Chairman, Sir, Andhra Pradesh is a newly formed State. The Government of India is supporting it. But, it requires further support. Are there any requests from the plantation sector as well as the commodity boards, like, the Coffee Board, the Tea Board, the Rubber Board, the Spices Board, expressing their willingness to offer sponsorship to the proposed IIPM? If yes, the details thereof. What infrastructural incentives are being proposed to be provided to such sponsoring boards?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Mr. Chairman, Sir, at the moment, the plantation sector is definitely involved in giving support mechanism to the IIPM, which exists at Bangalore and Jorhat and will certainly be extending the technical support for the Vijayawada Centre. But, other than that, if the hon. Member is referring to any industry support, we have not obtained anything as yet. So far as funding from the Centre is concerned, I think, I have answered it in the first part of the question itself.

नव-सृजित राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों की आवश्यकता

*423. **श्री महेन्द्र सिंह माहरा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की नव-सृजित राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों की स्थापना करने की योजनाएं हैं;

(ख) क्या नव-सृजित राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृति दी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन से कहां-कहां और कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना में कहां-कहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल खोले जाने का विचार है, उनकी सूची उपलब्ध कराएं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम सुधार कार्यसूची ईएसआईसी 2.0 के अनुसार, कर्मचारी राज्य

बीमा निगम की कवरेज का विस्तार किया जा रहा है। जहां कहीं बीमित व्यक्ति निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं, वहां नई चिकित्सा सुविधाएं सृजित की जा रही हैं जिसमें नव सृजित राज्य भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों में प्रस्तावित नए ईएसआई अस्पतालों और जारी की गई निधि का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

राज्य	नए ईएसआई अस्पतालों की अवस्थिति	अब तक जारी निधि (करोड़ रुपए में)
झारखंड	देवघर	—
छत्तीसगढ	रायपुर	4.54
	कोरबा	—
	भिलाई	—
उत्तराखंड	रुद्रपुर	10.74
	देहरादून	—
	हरिद्वार	—
	काशीपुर	—
तेलंगाना	—	—

Necessity of ESI hospitals in new States

†*423. SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has plans to establish ESI hospitals in newly formed States;

(b) whether approval for construction of ESI hospitals in the new States had been given earlier;

(c) if so, the details of the locations and the quantum of money released therefor; and

(d) if not, the proposed locations in Jharkhand, Chhattisgarh, Uttarakhand and Telangana for establishing ESI hospitals, the list thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND

† Original notice of the question was received in Hindi.

EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) reform agenda ESIC 2.0, the coverage under ESIC is being expanded. Wherever insured persons are more than the prescribed norms, new medical facilities are being created including in new States.

(b) to (d) The details of new ESI hospitals planned in the States of Jharkhand, Chhattisgarh, Uttarakhand and Telangana and funds released are as under:

States	Location of new ESI Hospitals	Funds released so far (₹ in crore)
Jharkhand	Deoghar	–
	Raipur	4.54
Chhattisgarh	Korba	–
	Bhilai	–
Uttarakhand	Rudrapur	10.74
	Dehradun	–
	Haridwar	–
	Kashipur	–
Telangana	–	–

श्री महेन्द्र सिंह माहराः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। इनमें से नौ पर्वतीय क्षेत्रों में और चार मैदानी क्षेत्रों में हैं। वहां रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं है। वहां हवाई जहाज से आने-जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। वहां लोगों को पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों में पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मानकों को शिथिल करते हुए, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में दो नए ESI अस्पताल खोलने पर विचार करेगी?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, the question is regarding the newly-formed States. The norms have been laid down for establishment of hospitals and dispensaries to cover such areas. Now, an expansion programme in ESIC is there. In the entire country, 681 districts are there, including hill areas. Out of them, when our Government came, 393

districts were partially covered. But now 393 districts are hundred per cent covered. Out of remaining 288 districts, in 85 districts, headquarters are covered and in the remaining 203 districts, survey is going on, and I am hopeful that in this expansion programme of ESIC, it can be done. The major concentration of this Government is on social security, particularly, on improving the quality of services for the benefit of our IPs. If some new proposal comes from the State Government, I will definitely examine.

श्री महेन्द्र सिंह माहराः सर, मैं माननीय मंत्री जी से अपने दूसरे प्रश्न में यह जानना चाहता हूँ कि देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में जो नए प्रस्तावित अस्पताल हैं, उनके लिए कब तक धन उपलब्ध हो जाएगा?

श्री बंडारू दत्तात्रेयः उत्तराखंड में अभी हम रुद्रपुर, देहरादून और हरिद्वार, इन तीन जगहों पर 100-bedded hospitals शुरू कर रहे हैं। आपने जो काशीपुर के बारे में पूछा है, तो वहाँ भी एक 100-bedded hospital के लिए proposal आया हुआ है। उसको भी हम सैंक्शन करेंगे और उसके लिए काम की तुरन्त शुरुआत करेंगे।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि नव-सृजित राज्य, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन् 2000 में बनाये गये थे और आज 2017 है। इन्होंने जो सूची दी है, उसके अनुसार 17 सालों में बहुत सारे एरियाज़ में, जहां पर उन हॉस्पिटल्स की मान्यता हुई है, उनके लिए पैसा नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि क्या इन राज्यों में अत्याधुनिक ESI Hospitals दिये जायेंगे, जिनके माध्यम से उन जगहों पर, जहाँ पिछड़ी जनजाति, आदिवासी और पहाड़ी लोग ज्यादा हैं, उनके लिए अच्छे superspeciality hospitals दिये जायेंगे?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, as I already said our expansion programme is there, particularly, in the North-East or even in the hilly areas wherever our IPs are there. I am happy to inform this august House that even in the period of demonetisation, we have taken up a new campaign, that is, 'Scheme to Promote Registration of Employers/ Employees'. It is called SPREE. We started it on 28th December, 2016. So far, we have covered 40,000 new establishments and 70,00,000 new IPs have been enrolled. Whatever sanctioned units are there, they are going to be completed by December, 2018 and whatever remaining proposal are there, we will examine them.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में नये ESI Hospitals खोलने के बारे में कहा है कि 'Whenever insured persons are more than the prescribed norms, उसके बाद ही शायद वे नये हॉस्पिटल्स वहाँ पर खोले जाएँगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो prescribed norms कहते हैं, तो नये ESI Hospitals खोलने के लिए वे prescribed norms आखिर क्या हैं?

श्री बंडारू दत्तात्रेयः सर, हमने इसके लिए जो prescribed norms बनाये हैं, उनके अनुसार जहाँ पर 3,000 IP family units रहते हैं, वहाँ पर हम 2 doctor dispensary की शुरुआत करेंगे, जहाँ

पर 5,000 IP family units रहते हैं, वहां पर 3 doctor dispensary खोलेंगे और जहां पर 10,000 IP family units रहेंगे, वहाँ पर 5 doctor dispensary खोलेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग अभी असंगठित मजदूरों, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, देश में करीब-करीब 4 करोड़ 30 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको भी informal sector से formal sector में लाये हैं। उनका भी नये रजिस्ट्रेशन में आया है। अब expansion programme में जैसे ही नंबर बढ़ता है, वैसे ही पहले से ही हमारी जो six-bedded dispensary है, उसको six-bedded hospital में कंवर्ट करना है। In that hospital itself, all primary treatment facilities, including minor operations, could be availed. As for the other norms, where there are 50,000 IPs, we are constructing 100-bedded hospitals; where there are one lakh IPs, we are constructing 150-bedded hospitals; where there are 1,50,000 IPs, we are constructing 200-bedded hospitals. In a similar way, we have norms for up to five lakh IPs, where we would be constructing 600-bedded hospitals. But, population within a radius of 25 kilometers should be considered and there should not be any other ESI hospital within the radius of 50 kilometres. This is also a norm. We are also trying to examine the distance of catchment hospitals.

MR. CHAIRMAN : Shri Punia.

श्रीमती छाया वर्माः सर, क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछ सकती हूँ?

श्री सभापतिः नहीं।

श्री पी.एल. पुनियाः सभापति जी, यह प्रश्न नए राज्यों में नए ESI हॉस्पिटल्स खोलने के संबंध में है। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने पूरे विस्तार से जानकारी तो नहीं दी, लेकिन कुछ सूचना दी है। नए अस्पताल तो खुलने चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ इसके लिए मेडिकल ऑफिसर्स की जो sanctioned strength है, वह भी पूरी होनी चाहिए। मेरे पास इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लोक सभा Unstarred Questoin 2979, जिसका जवाब 20 मार्च, 2017 को लोक सभा में दिया गया, जिसके अनुसार GDMO के 582 पद खाली हैं, Specialists के 386 पद खाली हैं, नर्सिंग और पैरामैडिकल के 4,560 पद खाली हैं, तो सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नए अस्पताल खोलने के साथ-साथ यह जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उसको किस तरह से पूरा करेंगे?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, the hon. Member has rightly pointed out that we have taken steps for augmenting manpower in medical services.

Now, as far as the question of 40 per cent of sanctioned posts under GDMO prescribed for ESI hospitals is concerned, all hospitals have Senior Residents appointed by Medical Superintendent at the local level. Secondly, ten posts of Senior Resident, for 100-bedded hospitals, have been sanctioned in addition to the above-mentioned posts of GDMO.

They are being filled up locally by Medical Superintendents. I am happy to inform, as far as paramedical and nursing posts are concerned, the Medical Superintendents have been authorized to engage, in certain situations, if necessary, even retired persons on a short-term basis. The other important point is that we have completed the process of recruiting 450 GDMOs and 304 Specialists. Regarding the special drive, as I have already intimated, doctors, nurses and paramedical staff are under training and we are progressing in that direction. The quality of services being provided also depends on the manpower.

Promotion of e-vehicles

424. SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government is considering to fine tune the plan to promote e-vehicles in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the surplus electricity available with the country, presently will be used in promoting e-vehicles; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) With a view to provide impetus to domestic manufacturing of hybrid and electric vehicles (collectively termed as xEVs), the Government of India approved the National Mission on Electric Mobility in 2011 and subsequently National Electric Mobility Mission Plan 2020 was unveiled in 2013. This Mission Plan has been designed mainly considering the Fuel Security and Environmental Pollution in the country.

In order to promote manufacturing of hybrid and electric vehicles and ensure sustainable growth of the same and as a follow up of the mission, Department of Heavy Industry (DHI) has formulated a scheme namely FAME India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India] for the initial period of two years starting from 1st April 2015 (Phase-1). In addition, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power has informed that Ministry of Power has also notified the fuel efficiency standards for passenger cars which provide super credits for electric vehicles.